[See Appendix CXCVII, Annexure No. 66]

(c) Central investments are made taking into consideration the techno-economic viability of projects while keeping in view the need for overall balanced regional development. Hence investment in different States cannot be of the same order.

Contract for the South Bassein Gasfield Development Project near Bombay

1581. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Governments attention has been drawn to the report of Sunday Observer of April 24 to 30, 1988, with regard to allotment of the contract for the BPB process complex of the South Bassein gasfield development project near Bombay in 1986;

(b) whether it is a fact that the second phase of the Rs. 600 crore South Bassein Project contract was not awarded to the South Korea's HHI which submitted the lowest quotation;

(c) whether it is a fact that contract went to the second lowest bidder; if so, what is the name of the second lowest bidder;

(d) what are the reasons for which the lowest bid was rejected; and

(e) what is the comment of the Audit Board which detected this irregularity?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The lowest evaluated offer on cash basis was that of M/s. Hyundai Heavy Industries, South Korea. The contract was, however, awarded to M/s. Snam Progetti, Italy as their offer was found to be cheaper, after taking into account the mixed credit offered by the firm alongwith their offer.

(e) Audit has, so far, only sought some information pertaining to the award of this contract.

झांसी टेलीफोन एक्सचेंज में "डायल प्रणाली"

1582. **डा० गोविन्द दास रिछारिया:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झांसी में टेलीफोन डायल प्रणाली आरम्भ करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है तथा इसके कब तक आरम्भ किये जाने की आशा है ; और

(ख) क्या बनाये जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंज में इलैक्ट्रानिक मशीनें लगाये जाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) झांसी में मौजूदा मैनुअल प्रणाली को आटोमैटिक बनाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है । 3000 लाइनों के आई. सी. पी. किस्म के आटोमैटिक एक्सचेंज के लिए उपस्कर के आदेश मैसर्स आई. टी. आई. रायबरेली को दे दिए गए हैं । सप्लाई चालू वर्ष के दौरान हो जाएगी । प्रस्तावित आटोमेटिक एक्सचेंज की स्थापना के लिए भवन पूरा होने वाला है । आई. सी. पी. एक्सचेंज के 90-91 के दौरान चालू होने की आशा है ।

(ख) जी नहीं । मांग की स्थिति के अनुसार झांसी में लगभग 2000-3000 लाइनों की क्षमता वाले एक्सचेंज की आवश्यकता है । चूंकि इस आकार में इलैक्ट्रानिक प्रणाली देश में उपलब्ध नहीं है अतः ठीक कुछ समय पहले आई. सी. पी. किस्म के एक्सचेंज की स्थापना की योजना मंजूर की गई थी और इसका काफी अग्रिम स्तर पर कार्यान्वयन किया जा रहा है । इस स्तर पर किसी प्रकार के परिवर्तन से अत्यावश्यक मैनुअल प्रणाली को आटोमैटिक बनाने में काफी विलंब होगा ।